

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

खंडपीठ सिविल रिट संख्या 12524/2022

सुशील कुमार पारीक पुत्र स्व. हनुमान सहाय पारीक, उम्र लगभग 66 वर्ष, निवासी 11/126, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर, जिला जयपुर, मुख्य आयुक्त उत्पाद शुल्क कार्यालय के अधीन सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पद से सेवानिवृत्त, जोन, जयपुर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. भारत संघ, अपने सचिव, भारत सरकार के माध्यम से, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।
2. 110023. अवर सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, 6वीं मंजिल, हुडको विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66. 110023।
3. मुख्य आयुक्त यदि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टेच्यू सर्कल, जयपुर (राजस्थान) 302005।
4. श्रीमती रुचिता विज्ञ, अतिरिक्त आयुक्त, जीएसटी और जांच अधिकारी कार्यालय आयुक्त, जी.एस.टी. न्यू सेंट्रल, राजस्व भवन, स्टेच्यू सर्किल, जयपुर (राजस्थान) 302005।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से	:	श्री सौरभ पुरोहित अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी की ओर से	:	श्री किंशुक जैन, श्री सौरभ जैन अधिवक्ता के साथ सीबीआई के वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता।

माननीय श्रीमान न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव

माननीय श्रीमान जस्टिस विनोद कुमार भरवानी

निर्णय

रिपोर्टबल

18/10/2022

सुना।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जयपुर खंडपीठ, जयपुर (इसके बाद 'न्यायाधिकरण' के रूप में संदर्भित) द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2022 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा आरोप-पत्र जारी कर विभागीय जांच की शुरुआत और संस्था को चुनौती दी गई है और मूल आवेदन खारिज कर दिया गया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ताने तर्क दिया कि अपीलार्थी को कथित भ्रष्टाचार के कुछ आरोपों के आधार पर विभागीय जांच के अधीन किया जा रहा है, जिसमें जांच में प्रस्तावित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं, जो कि आरोप तय करने के चरण में दंड न्यायालय द्वारा विचार का विषय था। 2016 के आपराधिक नियमित मामले संख्या 5 (सी.बी.आई. बनाम सुशील कुमार पारीक और अन्य के माध्यम से सरकार) में विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले संख्या 1, जयपुर (राजस्थान) द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.04.2017 का हवाला देते हुए, हमारे सामने यह तर्क दिया गया है अभियोजन का पूरा आरोप, जो या तो मकसद या इनाम के रूप में रिश्त के इर्द-गिर्द घूमता है, पर विस्तार से विचार किया गया और सीबीआई न्यायालय के समक्ष सीबीआई द्वारा दायर आरोप-पत्र में शामिल सामग्री की सूक्ष्म जांच के बाद, दंड न्यायालय ने पाया कि यह कोई आरोप लगाने के योग्य नहीं था। यहां तक कि मामला आरोप तय करने लायक भी है। इसलिए, जहां दंड न्यायालय ने आपराधिक मामले में दायर आरोप-पत्र में निहित सामग्री की गहन जांच के बाद पाया है कि अभियोजन का मामला आगे भी नहीं बढ़ सका क्योंकि आरोप तय करने योग्य भी नहीं थे, यह न्याय का मखौल होगा कि आरोपों, मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के एक ही सेट पर विभाग को विभागीय जांच के तहत मामले को फिर से खोलने की अनुमति है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दंड न्यायालय द्वारा अभियोजन मामले को बिना किसी आधार के पाया गया था क्योंकि सीबीआई दो असंगत कहानियों के साथ सामने आई थी, एक मकसद की और दूसरी इनाम की, जो पूरी तरह से असंगत पाई गई और जिसने दंड न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आपराधिक आरोपों से मुक्त करने का आधार बनाया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि यह ऐसा मामला नहीं है जहां न्यायालय को सबूत के विभिन्न मानकों के आधार पर सिद्धांत लागू करने की आवश्यकता है, बल्कि यह एक ऐसा मामला है जहां प्रथम दृष्टया आधार पर भी, दंड न्यायालय द्वारा आपराधिक मामला

शुरू करने लायक कोई मामला नहीं पाया गया। कोर्ट ने कहा, ऐसी स्थिति में विभागीय जांच शुरू करना ही व्यर्थ की कवायद है। अपनी दलीलों के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कैप्टन एम. पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड और अन्य, (1999) 3 679 और जी.एम. टैंक बनाम गुजरात सरकार और अन्य, (2006) 5 उच्चतम न्यायालय के 446 मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा जताया है।

इसके विपरीत, प्रत्यथियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विद्वान न्यायाधिकरण ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर उचित विचार करने के बाद, विशेष रूप से आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और दंड न्यायालय द्वारा पारित आदेश को भी ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विभागीय जांच को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि आपराधिक मामले से मुक्ति मिल गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचते समय, न्यायाधिकरण ने मामले में सही सिद्धांत लागू किए हैं और वर्तमान में यह किसी न्यायिक त्रुटि का मामला नहीं है। एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (1997) 3 उच्चतम न्यायालय मामले 261 और साधना लोध बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य, (2003) 3 उच्चतम न्यायालय न्यायालय प्रकरण 524 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, कहा कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध हस्तक्षेप के मामले में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सीमित है और कानून या तथ्य की त्रुटि को हस्तक्षेप का आधार नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है।

अन्यथा भी, यह तर्क दिया जाता है, वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश किए गए सबूतों की पूरी सुनवाई और जांच के बाद, जो बरी होने पर समाप्त हुआ, सबूतों के उसी सेट को विभागीय जांच में ले जाने का प्रस्ताव है, इसलिए, निर्णय जी.एम. के मामलों में टैंक (सुप्रा.) के साथ-साथ कैप्टन एम. पॉल एंथोनी (सुप्रा.) कोई सहायता नहीं कर रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सड़क परिवहन निगम बनाम दिलीप उत्तम जयभाय, (2022) 2 उच्चतम न्यायालय मामले 696 और कर्नाटक सरकार और अन्य बनाम उमेश, (2022) 6 उच्चतम न्यायालय मामले 563 के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि जहां आपराधिक मामले भी स्थापित, लंबित या निर्णयित हैं, वहां विभागीय जांच कराने की अनुमति के

संबंध में सिद्धांत अच्छी तरह से तय हैं। ट्रिब्यूनल ने अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटि या विकृति नहीं की है, इसलिए आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

हमने पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना है और रिकॉर्ड पर मौजूद पूरी सामग्री को देखा है, विशेष रूप से आरोप-पत्र, अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप का बयान, दंड न्यायालय द्वारा पारित आदेश और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश भी।

विभागीय जांच में अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों और आरोपों का विवरण, जिनका हमारे समक्ष विरोध किया गया है, वे इस प्रकार हैं:-

आरोप की धाराओं का विवरण:-

श्री सुशील कुमार पारीक सहायक के पद पर पदस्थ रहते हुए आईसीडी, कॉनकोर, जयपुर में सीमा शुल्क आयुक्तने सुनील कुमार शर्मा एवं श्री लाला राम शर्मा ने साजिश करके रूप नारायण शर्मा मैसर्स के जब्त तीन कंटेनरों को छुड़ाएंगे। आर.एन. मेटल्स प्रा. लिमिटेडके तीन जब्त कंटेनरों को जयपुर से कॉनकोर, आईसीडी, कनकपुरा, जयपुर (सामग्री का संरक्षक) जिसे सीमा शुल्क द्वारा जब्त कर लिया गया था और मैसर्स कॉनकोर, जयपुर की हिरासत में रखा गया था को छुड़ाने के लिए श्री रूप नारायण शर्मा से इनाम के रूप में 2 लाख रुपये की रिश्त की मांग की। इसलिए, वह पूर्ण सत्यनिष्ठा और कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखने में विफल रहा और एक सरकारी कर्मचारी के रूप में अनुचित तरीके से आचरण किया, और इस प्रकार केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3(1)(i), 3(1)(ii) और 3(1)(iii) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और केंद्रीय सिविल सेवा (सीसीए) नियम, 1965 के नियम 14 के तहत कार्रवाई के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया।

“श्री सुशील कुमार पारीक, सहायक आयुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की

धाराओं के समर्थन में कदाचार के आरोप का विवरण:-

श्री सुशील कुमार पारीक, जब आईसीडी, कॉनकोर, जयपुर में सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त के रूप में तैनात थे, उन्होंने श्री सुनील कुमार

शर्मा एवं श्री लाला राम शर्मा ने श्री रूप नारायण शर्मा के साथ साजिश रची और मैसर्स रूप नारायण शर्मा के जब्त तीन कंटेनरों को छुड़ाने के लिए इनाम के रूप में 2 लाख रुपये की रिश्त की मांग की। आर.एन. मेटल्स प्रा. लिमिटेड, जयपुर से कौनकोर, आईसीडी, कनकपुरा, जयपुर (सामग्री का संरक्षक) जिसे सीमा शुल्क द्वारा जब्त कर लिया गया था और मैसर्स कौनकोर, जयपुर की हिरासत में रखा गया था को छुड़ाने के लिए 2 लाख रुपये की रिश्त इनाम के रूप में मांगी।

अपीलार्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप की धाराओं के समर्थन में कदाचार के आरोप के बयान का विवरण पैराग्राफ 3 से 54 में निहित है। आरोप-पत्र के साथ संलग्न तीसरा अनुलग्नक उन दस्तावेजों की सूची देता है जिनके द्वारा आरोपों की धाराएं हैं सिद्ध करने का प्रस्ताव है, जिनकी संख्या 51 है। चौथा अनुबंध 15 गवाहों की सूची है जिनसे विभाग द्वारा मौखिक साक्ष्य लेकर आरोपों को साबित करने का प्रस्ताव है।

विभागीय जांच शुरू करने को अपीलार्थी की चुनौती इस तर्क पर आधारित नहीं है कि यदि संपूर्ण आरोप-पत्र और आरोपों के बयानों को वैसे ही लिया जाए, तो भी वे कदाचार नहीं बनते हैं, लेकिन उनका मामला यह है कि दंड न्यायालय आदेश के बाद, अपीलार्थी को आपराधिक आरोपों से मुक्त किए जाने के कारण, विभागीय जांच जारी नहीं रखी जा सकती क्योंकि यह केवल एक औपचारिकता होगी और अनिवार्य रूप से दंड न्यायालय के निष्कर्षों के विरुद्ध जाएगी।

दंड न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दाखिल करके अपीलार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामले की स्थापना की जांच की गई। संबंधित न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 15.04.2017 के आदेश द्वारा माना कि अभियोजन का मामला मुख्य रूप से इस आधार पर संदेह में है कि अभियोजन मामले में असंगतता है। हालाँकि, इन कार्यवाहियों में, हम दंड न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यता और वैधता पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें सूचित किया गया है कि अपीलार्थी को बरी करने के लिए सीबीआई न्यायालय द्वारा पारित आदेश पर सक्षम न्यायालय में पुनरीक्षण दायर करके चुनौती दी गई है जो अभी भी विचाराधीन है, हम केवल यह उजागर करने का प्रस्ताव करते हैं कि अपीलार्थी को आरोप मुक्त करने का आदेश मुख्य रूप से अभियोजन की कहानी में असंगतता पर

आधारित था, जैसा कि सीबीआई कोर्ट ने नोटिस किया।

यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष ने पुरस्कार की कहानी बताई और इसीलिए सिद्धांत रूप से इस कारण से ही सीबीआई अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप तय करने की इच्छुक नहीं थी लेकिन जो भी हो, मामला पुनरीक्षण न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे।

प्रश्न, जो विचार के लिए उठता है, वह यह है कि क्या केवल दंड न्यायालय के समक्ष पेश किए गए बिना किसी सबूत के आरोपमुक्त करने पर, विभाग को आरोपों और मौखिक और दस्तावेजी सबूतों के सेट पर अपीलार्थी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने से भी रोक दिया जाता है, जो अपीलार्थी के विरुद्ध प्रस्तावित है।

कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक ओर विभागीय जांच और दूसरी ओर एक आपराधिक मामला पूरी तरह से अलग-अलग स्तर पर होता है। सबूत के मानक और स्तर, जो विभागीय जांच में आवश्यक हैं, केवल संभाव्यता की प्रधानता है, जिसके विरुद्ध एक आपराधिक मामले में सबूत की आवश्यकता उचित संदेह से परे है क्योंकि दोषसिद्धि अंततः व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन की ओर ले जाती है। इसलिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णयों में जो व्यापक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं, वे यह हैं कि केवल इसलिए कि कोई आपराधिक आरोप है या बरी कर दिया गया है, सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तनीय प्रकृति और सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं है कि कोई विभागीय जांच नहीं हो सकती। यह हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

जी.एम.टैंक (सुप्रा.) और कैप्टन एम. पॉल एंथोनी (सुप्रा.), के मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा रखा गया।

तथ्यों के आधार पर, कैप्टन एम. पॉल एंथोनी (सुप्रा.) के मामले में, अपीलार्थी को आपराधिक मामले में स्पष्ट निष्कर्ष के साथ बरी कर दिया गया था कि अभियोजन पक्ष अपना मामला स्थापित करने में विफल रहा। इस बीच, अपीलार्थी को अनुशासनात्मक कार्यवाही के आधार पर पहले ही सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जो पहले उसके विरुद्ध शुरू की गई थी। उस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में विभागीय कार्यवाही और कार्यवाही के बीच परस्पर क्रिया के संबंध में कानून बनाते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया:-

“22. उपरोक्त उल्लिखित इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से जो निष्कर्ष निकलते हैं वे इस प्रकार हैं:

(i) किसी आपराधिक मामले में विभागीय कार्यवाही और कार्यवाही एक साथ चल सकती हैं क्योंकि उन्हें अलग-अलग होने पर भी एक साथ चलाने पर कोई रोक नहीं है।

(ii) यदि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक मामला समान और समान तथ्यों पर आधारित है और अपराधी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामले में आरोप गंभीर प्रकृति का है जिसमें कानून और तथ्य के जटिल प्रश्न शामिल हैं, तो आपराधिक मामले के समापन तक विभागीय कार्यवाही को स्थगित करना वांछनीय होगा।

(iii) क्या किसी आपराधिक मामले में आरोप की प्रकृति गंभीर है और क्या उस मामले में तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हैं, यह अपराध की प्रकृति, जुटाए गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर कर्मचारी के विरुद्ध जांच के दौरान या आरोप-पत्र में दर्शाए अनुसार शुरू किए गए मामले की प्रकृति पर निर्भर करेगा।

(iv) विभागीय कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए ऊपर (ii) और (iii) में उल्लिखित कारकों पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि विभागीय कार्यवाही में अनावश्यक देरी नहीं की जा सकती है।

(v) यदि आपराधिक मामला आगे नहीं बढ़ता है या उसके निपटान में अनावश्यक देरी हो रही है, तो विभागीय कार्यवाही, भले ही आपराधिक मामले के लंबित रहने के कारण रोक दी गई हो, फिर से शुरू की जा सकती है और आगे बढ़ाई जा सकती है ताकि उन्हें शीघ्र तिथि पर समाप्त किया जा सके, ताकि यदि कर्मचारी दोषी नहीं पाया जाता है तो उसका सम्मान बचाया जा सके और यदि वह दोषी पाया जाता है, तो प्रशासन उसे जल्द से जल्द छुटकारा दिला सके।”

उस निर्णय के पैरा 34 में तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि आपराधिक मामला और विभागीय कार्यवाही भी समान तथ्यों पर आधारित थीं। आगे यह देखा गया

कि दोषी कर्मचारी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को पुलिस अधिकारियों और पंच गवाहों द्वारा साबित करने की मांग की गई थी, जिन्होंने घर पर छापा मारा था और बरामदगी की थी। वे एकमात्र गवाह थे जिनकी जांच अधिकारी द्वारा जांच की गई और जांच अधिकारी उन्हीं गवाहों के बयानों पर भरोसा करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप स्थापित किए गए थे। आपराधिक मामले में एकमात्र उन्हीं गवाहों की जांच की गई लेकिन दंड न्यायालय, पूरे साक्ष्य पर विचार करने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दोषी कर्मचारी के आवास से कोई तलाशी नहीं ली गई और न ही कोई बरामदगी की गई और अभियोजन का मामला पूरी तरह से विफल हो गया जिससे दोषी कर्मचारी को बरी कर दिया जाएगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय का दूसरा निर्णय जी.एम. टांक (सुप्रा.) के मामले में बरी होने से संबंधित था। तथ्यों के आधार पर, यह एक ऐसा मामला था जहां एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोषी कर्मचारी के विरुद्ध जांच की, जिसके कारण आरोप पत्र दाखिल किया गया, उसके विरुद्ध एक विभागीय जांच भी शुरू की गई और उसे आरोपों का दोषी पाया गया। हालाँकि, आपराधिक मामले में दोषी कर्मचारी को बरी कर दिया गया। ऐसी पृष्ठभूमि में, विचार के लिए उठने वाले प्रश्नों में से एक यह था कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत विशेष न्यायालय द्वारा अपराधी को स्पष्ट रूप से दोषमुक्त करने के लिए गुणागुण के आधार पर बरी करना वास्तव में अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के तहत अपराधी को दायित्व से मुक्त कर देता है, जबकि विभागीय कार्यवाही और आपराधिक कार्यवाही में अपराधी के विरुद्ध लगाए गए आरोप तथ्यों, परिस्थितियों और सबूतों के समान सेट पर आधारित हों। उस मामले के तथ्यों पर, कैप्टन एम. पाल एंथोनी (सुप्रा.) के मामले में और अन्य निर्णयों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के पहले के निर्णय पर भरोसा करते हुए, जहां साफ बरी कर दिया जाता है। एम. पॉल एंथोनी (सुप्रा.), और अन्य निर्णय, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि विभागीय जांच में पारित आदेश कानून की नजर में टिक नहीं सका, जिसके कारण अंततः विभागीय जांच में पारित आदेश को रद्द कर दिया गया। उस मामले में भी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कैप्टन एम. पॉल एंथोनी (सुप्रा.), आर.पी. कपूर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य, एआईआर 1964 एससी 787, कॉर्पोरेशन ऑफ नागपुर शहर, सिविल लाइन्स, नागपुर और अन्य बनाम रामचन्द्रजी. मोदक और अन्य, एआईआर 1984 एससी 626, अजीत कुमार नाग बनाम महाप्रबंधक (पीजे), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया और अन्य, (2005) 7 उच्चतम

न्यायालय केस 764 और इसी प्रकार डिपो मैनेजर, ए.पी. सरकार सड़क परिवहन निगम बनाम मो. यूसुफ मिया और अन्य, (1997) 2 उच्चतम न्यायालय मामले 699 के मामलों में निर्धारित सामान्य सिद्धांतों के लागू होने की जांच की। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा देखा गया सार्वभौमिक प्रयोग का सिद्धांत यह था कि कानून सुस्थापित है कि दंड न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर नियोक्ता को लागू नियमों और विनियमों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोका जाएगा। दोनों कार्यवाही अर्थात् आपराधिक और विभागीय पूरी तरह से अलग हैं। वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। जहां आपराधिक मुकदमे का उद्देश्य अपराधी को उचित दंड देना है, वहीं जांच कार्यवाही का उद्देश्य अपराधी से विभागीय तौर पर निपटना और सेवा नियमों के अनुसार जुर्माना लगाना है। एक आपराधिक मुकदमे में, कुछ परिस्थितियों में या कुछ अधिकारियों के समक्ष अभियुक्त द्वारा दिया गया अभियोगात्मक बयान साक्ष्य में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। साक्ष्य और प्रक्रिया के ऐसे सख्त नियम विभागीय कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। दोषसिद्धि का आदेश देने के लिए आवश्यक सबूत की डिग्री अपराध के कमीशन को रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक सबूत की डिग्री से भिन्न होती है। दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित नियम भी समान नहीं हैं। आपराधिक कानून में, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है और जब तक अभियोजन उचित संदेह से परे अभियुक्त के अपराध को साबित करने में सक्षम नहीं होता है, तब तक उसे न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। दूसरी ओर, विभागीय जांच में, संभाव्यता की प्रबलता के आधार पर दर्ज किए गए निष्कर्ष पर दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए, दंड न्यायालय द्वारा अपराधी को बरी कर देना वास्तव में उसे नियोक्ता के अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के तहत दायित्व से मुक्त नहीं करता है।

इसलिए, अपीलार्थी का मामला **जी.एम. टैंक (सुप्रा.) और कैप्टन एम. पॉल एंथोनी (सुप्रा.)** के मामलों की तुलना में तथ्यों पर अलग-अलग पायदान पर खड़ा है।

जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, व्यापक सिद्धांतों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बार-बार दोहराया गया है। **कर्नाटक सरकार और अन्य बनाम उमेश (सुप्रा.)** के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले निर्धारित सिद्धांतों को दोहराया गया है और इसे निम्नानुसार माना गया है:-

16. अनुशासनात्मक जांच को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत उन सिद्धांतों से भिन्न होते हैं जो आपराधिक मुकदमे पर लागू होते हैं। आपराधिक कानून

के तहत दंडनीय अपराध के लिए अभियोजन में, उचित संदेह से परे अपराध की सामग्री को स्थापित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है। अभियुक्त निर्दोषता की अवधारणा का हकदार है। नियोक्ता द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही का उद्देश्य किसी कर्मचारी द्वारा कदाचार के आरोप की जांच करना है जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के संबंध को नियंत्रित करने वाले सेवा नियमों का उल्लंघन होता है। एक आपराधिक अभियोजन के विपरीत जहां आरोप को उचित संदेह से परे स्थापित किया जाना है, एक अनुशासनात्मक कार्यवाही में, कदाचार का आरोप संभावनाओं की प्रधानता पर स्थापित किया जाना है। साक्ष्य के नियम जो आपराधिक मुकदमे पर लागू होते हैं वे उन नियमों से भिन्न होते हैं जो अनुशासनात्मक जांच को नियंत्रित करते हैं। किसी आपराधिक मामले में आरोपी को बरी करने से नियोक्ता को अनुशासनात्मक क्षेत्राधिकार के प्रयोग में आगे बढ़ने से रोका नहीं जाता है।

17. हरियाणा सरकार बनाम रतन सिंह, (1977) 2 उच्चतम न्यायालय केस 491, वी. आर. कृष्णा अय्यर, जे. में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में अनुशासनात्मक कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं: (एससीसी) पृ.493, पैरा 4)

"4. यह अच्छी तरह से तय है कि घरेलू जांच में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत साक्ष्य के सख्त और परिष्कृत नियम लागू नहीं हो सकते हैं। वे सभी सामग्रियां जो विवेकपूर्ण दिमाग के लिए तार्किक रूप से संभावित हैं, स्वीकार्य हैं। सुनी-सुनाई बातों से कोई एलर्जी नहीं है, बशर्ते उसमें उचित सांठ-गांठ और विश्वसनीयता हो। यह सच है कि विभागीय अधिकारियों और प्रशासनिक न्यायाधिकरणों को ऐसी सामग्री का मूल्यांकन करने में सावधानी बरतनी चाहिए और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रासंगिक नहीं होने वाली चीजों को लापरवाही से नहीं मानना चाहिए। इस प्रतिपादन के लिए न तो निर्णयों और न ही पाठ्य पुस्तकों का हवाला देना आवश्यक है, हालांकि हमें दोनों पक्षों के अधिवक्ता द्वारा निर्णय-विधि और अन्य अधिकारियों के माध्यम से अवगत कराया गया है। न्यायिक दृष्टिकोण का सार निष्पक्षता, बाहरी सामग्रियों

या विचारों का बहिष्कार और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन है। निःसंदेह, निष्पक्षता ही आधार है और यदि विकृति या मनमानी, पूर्वाग्रह या निर्णय की स्वतंत्रता का समर्पण, पहुंचे हुए निष्कर्षों को खराब करता है, तो घरेलू न्यायाधिकरण के बावजूद भी इस तरह के निष्कर्ष को अच्छा नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, निचली अदालतों ने शायद इस बात पर जोर देकर खुद को गलत दिशा दी है कि जो यात्री अंदर आए थे और बाहर गए थे, उनका पीछा किया जाना चाहिए और वैध निष्कर्ष दर्ज किए जाने से पहले ट्रिब्यूनल के सामने लाया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने जिस 'अवशिष्ट' नियम का उल्लेख किया, वह अमेरिकी न्यायशास्त्र के कुछ अंशों पर आधारित है उस सीमा तक नहीं जाता है और न ही हैल्सबरी का लेखांश ऐसी कठोर आवश्यकता पर जोर देता है। सीधी बात यह है कि क्या कोई सबूत था या कोई सबूत नहीं था- नियमित अदालती कार्यवाही को नियंत्रित करने वाले तकनीकी नियमों के अर्थ में नहीं, बल्कि निष्पक्ष सामान्य ज्ञान के तरीके से, जैसा कि समझदार और सांसारिक ज्ञान वाले लोग स्वीकार करेंगे। इस तरह से देखने पर, घरेलू न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्ष के सबूत में साक्ष्य की पर्याप्तता जांच से परे है। किसी निष्कर्ष के समर्थन में किसी भी सबूत का अभाव निश्चित रूप से न्यायालय के लिए उपलब्ध है क्योंकि यह रिकॉर्ड पर स्पष्ट कानून की त्रुटि है। इस मामले में हम पाते हैं कि फ्लाइंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर चमनलाल की गवाही कुछ ऐसे सबूत हैं जिनकी प्रत्यर्थी के विरुद्ध लगाए गए आरोप से प्रासंगिकता है। इसलिए, हम यह मानने में असमर्थ हैं कि आदेश उस आधार पर अमान्य है।"

(मूल पर बल और आपूर्ति)

इन सिद्धांतों को इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में दोहराया गया है जिनमें राजस्थान सरकार बनाम बी के मीना (1996) 6 उच्चतम न्यायालय मामले 417; कृष्णकाली टी एस्टेट बनाम अखिल भारतीय चाय मजदूर संघ, (2004) 8 उच्चतम न्यायालय मामले 200; अजीत कुमार नाग बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (2005) 7 उच्चतम न्यायालय मामले 764 और सीआईएसएफ बनाम अबरार अली, (2017) 4 उच्चतम न्यायालय मामले 507 शामिल हैं।

18. दलीलों के दौरान, प्रत्यर्थियों ने भारत संघ बनाम ज्ञान चंद चत्तर, (2009) 12 उच्चतम न्यायालय केस 78 के निर्णय पर भरोसा जताया। उस मामले में, प्रत्यर्थी के विरुद्ध छह आरोप तय किए गए थे एक आरोप यह था कि उन्होंने रेलवे कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए 1% कमीशन की मांग की थी। जांच अधिकारी ने सभी छह आरोप सिद्ध पाए। अनुशासनात्मक प्राधिकारी उन निष्कर्षों से सहमत हुए और निचली रैंक पर प्रत्यावर्तन की सजा दी। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि यह मानने के लिए कोई सबूत नहीं है कि वह रिश्त के आरोप का दोषी था क्योंकि गवाहों ने केवल यह कहा था कि भुगतान न करने का मकसद/कारण एक कमीशन राशि की अपेक्षा हो सकती है। प्रत्यर्थी ने निर्णय के निम्नलिखित अंशों पर भरोसा जताया: (एससीसी पृष्ठ 85 और 87, पैरा 21 और 31)

"21. भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप को पूरी तरह से साबित करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे संबंधित कर्मचारी पर सिविल और आपराधिक दोनों परिणाम आते हैं। उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है और ऐसे मामलों में उसे कड़ी से कड़ी सजा भी भुगतनी पड़ सकती है। इसलिए, अर्ध-आपराधिक प्रकृति के ऐसे गंभीर आरोप को संदेह की छाया से परे और पूरी ताकत से साबित करने की आवश्यकता थी। इसे केवल संभावनाओं के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सकता।

31. जिसमें यह माना गया है कि सजा हमेशा कदाचार की गंभीरता के अनुपात में होनी चाहिए। हालाँकि, भ्रष्टाचार के मामले में एकमात्र सजा सेवा से बर्खास्तगी है। इसलिए, भ्रष्टाचार के आरोप को हमेशा यह ध्यान में रखते हुए निपटाया जाना चाहिए कि इसके सिविल और आपराधिक दोनों परिणाम होते हैं।"

19. ज्ञान चंद चत्तर मामले के पैरा 21 में की गई टिप्पणियाँ मामले का अनुपातिक निर्णय नहीं हैं। हाईकोर्ट के निर्णय पर चर्चा के दौरान ये टिप्पणियाँ की गईं। निर्णय का अनुपात निर्णय के बाद के अंशों में उभरता है, जहां रतन सिंह में निर्धारित प्रासंगिक सामग्री और प्राकृतिक न्याय के अनुपालन का परीक्षण दोहराया गया था: (ज्ञान चंद चत्तर मामला, एससीसी पृष्ठ 88, पैरा 35 -36)

"35....वैधानिक प्रावधानों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जानी है। आरोप

विशिष्ट, निश्चित होने चाहिए और उस घटना का विवरण देना चाहिए जिसने आरोपों का आधार बनाया। अस्पष्ट आरोपों पर कोई भी जांच कायम नहीं रखी जा सकती। जांच निष्पक्षता से, वस्तुपरक ढंग से की जानी चाहिए न कि व्यक्तिपरक ढंग से। निष्कर्ष विकृत या अनुचित नहीं होना चाहिए, न ही अनुमानों और धारणाओं पर आधारित होना चाहिए। प्रमाण और संदेह में अंतर है। अपराधी की ओर से प्रत्येक कार्य या चूक कदाचार नहीं हो सकती। प्राधिकारी को कदाचार को परिभाषित करने वाले कानून के संदर्भ में तथ्य की खोज पर पहुंचने के लिए कारणों को दर्ज करना चाहिए।

36. वास्तव में, प्रत्यर्थी के विरुद्ध जांच शुरू करना वरिष्ठ अधिकारियों की पीड़ा का परिणाम प्रतीत होता है क्योंकि रेलवे कर्मचारियों द्वारा वेतन और भत्ते के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था और उन्होंने ट्रेन को अवैध रूप से रोका था और ऐसा भी हुआ था रेलवे स्टेशन पर कई घंटों तक हंगामा हुआ। जांच अधिकारी ने गैर-मौजूदा सामग्री को ध्यान में रखा है और प्रासंगिक सामग्री पर विचार करने में विफल रहा है। उनके द्वारा दर्ज किए गए सभी तथ्यों को कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता है।"

(जोर दिया गया)

भ्रष्टाचार के आरोप पर, न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में पाया कि प्रत्यर्थी की सजा को बनाए रखने के लिए कोई प्रासंगिक सामग्री नहीं थी क्योंकि केवल सुनी-सुनाई साक्ष्य थे जहां गवाहों ने माना कि रेलवे कर्मचारियों को भुगतान न करने का मकसद भ्रष्टाचार हो सकता है। इसलिए, विभागीय कार्यवाही की वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायालय द्वारा जो मानक लागू किया गया था वह यह था कि क्या (i) निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए प्रासंगिक सामग्री थी; और (ii) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया गया।

20. कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम वी. सी. नागराजू, (2019) 10 उच्चतम न्यायालय मामले 367 में, इस न्यायालय ने माना है: (एससीसी पृष्ठ 371, पैरा 9)

"9. दंड न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से नियोक्ता को नियमों और विनियमों के अनुसार विभागीय कार्यवाही संचालित करने की शक्ति का प्रयोग

करने से नहीं रोका जाएगा। दोनों कार्यवाही, आपराधिक और विभागीय, पूरी तरह से अलग हैं। वे अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उनके अलग-अलग उद्देश्य होते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही में, सवाल यह है कि क्या प्रत्यर्थी ऐसे आचरण का दोषी है जिसके लिए उसे सेवा से हटाया जा सकता है या कम सजा दी जा सकती है, जैसा भी मामला हो, जबकि आपराधिक कार्यवाही में, सवाल यह है कि क्या उसके विरुद्ध अपराध दर्ज किए गए हैं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम स्थापित किया गया है, और यदि स्थापित किया गया है, तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए। सबूत के मानक, जांच का तरीका और दोनों मामलों में जांच और मुकदमे को नियंत्रित करने वाले नियम काफी अलग और भिन्न हैं।”

21. न्यायालय ने यह भी माना कि: (सी. नागराजू मामला, एससीसी पृष्ठ 372, पैरा 13)

“13. अपीलार्थी और प्रत्यर्थी¹ की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी के आदेश में हस्तक्षेप अनुचित था। यह स्थापित कानून है कि दंड न्यायालय द्वारा बरी किए जाने से दोषी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय जांच रोकी जा सकती है। यदि विभागीय जांच में पेश किया गया साक्ष्य आपराधिक मुकदमे के दौरान पेश किए गए साक्ष्य से भिन्न है तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी दंड न्यायालय के निर्णय से बाध्य नहीं है। विभागीय जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या अपराधी आचरण नियमों के तहत कदाचार का दोषी है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उसे सेवा में जारी रखा जाना चाहिए। विभागीय जांच में सबूत का मानक पूरी तरह से साक्ष्य के नियमों पर आधारित नहीं है। बर्खास्तगी का आदेश, जो अनुशासनात्मक कार्यवाही में जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य पर आधारित है, जो कि दंड न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य से अलग है, उचित है और इसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

महाराष्ट्र सरकार सड़क परिवहन निगम बनाम दिलीप उत्तम जयभाय (सुप्रा.) के मामले में एक अन्य निर्णय में, उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त सिद्धांतों पर प्रकाश डाला और नीचे दिए गए सिद्धांतों को दोहराया:-

“11.3. औद्योगिक न्यायालय द्वारा बहुत अधिक बल दिया गया है कि दंड न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को बरी किये जाने पर हालाँकि, श्रम न्यायालय ने दंड न्यायालय द्वारा पारित बरी करने के आदेश पर व्यापक रूप से विचार किया था और प्रत्यर्थी - कामगार की ओर से की गई दलीलों से सहमत नहीं था कि चूँकि उसे दंड न्यायालय ने बरी कर दिया था, इसलिए अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

11.4 दंड न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश से भी ऐसा प्रतीत होता है कि दंड न्यायालय ने गवाहों के मुकर जाने; इच्छुक गवाहों के द्वारा साक्ष्य; जांच अधिकारी की जांच में कमी; घटना के स्थान का पंचनामा आदि के लिए पंच के आधार पर प्रत्यर्थी को बरी कर दिया गया था। इसलिए, दंड न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे प्रत्यर्थी के विरुद्ध मामले को साबित करने में विफल रहा है। इसके विपरीत विभागीय कार्यवाही में तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने का दुराचार जिससे दुर्घटना हुई तथा जिसके कारण चार व्यक्तियों की मृत्यु हुई, प्रमाणित एवं सिद्ध हो चुका है। कानून के मूलभूत सिद्धांत के अनुसार किसी आपराधिक मुकदमे में बरी होने का अनुशासनात्मक कार्यवाही पर कोई प्रभाव या प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि दोनों मामलों में सबूत के मानक अलग-अलग हैं और कार्यवाही अलग-अलग क्षेत्रों में और अलग-अलग उद्देश्यों के साथ चलती है। इसलिए, औद्योगिक न्यायालय ने दंड न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को बरी करने पर अधिक जोर देकर गलती की है। अन्यथा भी यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि औद्योगिक न्यायालय ने विभागीय जांच में साबित हुए आरोप और कदाचार को मानते हुए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं किया है, और केवल इस आधार पर बर्खास्तगी की सजा में हस्तक्षेप किया है कि यह आश्चर्यजनक रूप से अनुपातहीन है। और इसलिए एमआरटीयू और पीयूएलपी अधिनियम, 1971 की अनुसूची-IV” के खंड क्रमांक 1 (जी) के अनुसार एक अनुचित श्रम व्यवहार कहा जा सकता है।

वर्तमान मामले में, हम पाते हैं कि विभागीय जांच की शुरुआत को चुनौती देने के

लिए अपीलार्थी का पूरा जोर और जोर आरोपमुक्त करने के आदेश पर आधारित है। वे सिद्धांत, जो आरोप तय करने के चरण में दंड न्यायालय द्वारा विचार के मामले में लागू होते हैं, अनिवार्य रूप से आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत तैयार किए गए हैं। दंड न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विचार कर रहा था और इस बात पर भी विचार कर रहा था कि क्या अभियोजन का मामला आपराधिक मामला शुरू करने लायक है। विभागीय जांच को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए उसी सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में ऐसा कोई मामला भी नहीं है जहां दंड न्यायालय में गवाहों की जांच की गई हो और उनके साक्ष्यों की बारीकी से जांच की गई हो, आपराधिक मामले में अभियोजन साक्ष्य को मनगढ़ंत कहानी के रूप में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया हो।

विभागीय जांच शुरू करने के मामले में लागू सिद्धांत उन सिद्धांतों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं जो आपराधिक कार्यवाही में आरोप तय करने के चरण में लागू होते हैं।

हमने पाया कि दंड न्यायालय ने आरोप तय करने से इनकार कर दिया क्योंकि अभियोजन की कहानी में कुछ असंगतता थी। विभागीय जांच में, संभाव्यता की प्रधानता के सिद्धांतों को लागू करने पर, कर्मचारी के विरुद्ध विभाग द्वारा दिए गए सबूत से आरोप साबित हो सकते हैं क्योंकि आपराधिक मामले में आवश्यक उच्च स्तर का सबूत बिल्कुल भी लागू नहीं होता है। यह नहीं माना जा सकता कि विभागीय जांच में भी अभियोजन पक्ष असंगत या विरोधाभासी साक्ष्य पेश करेगा।

अपीलार्थी द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार करने के लिए विद्वान न्यायाधिकरण ने वर्तमान मामले में मामले से निपटने में सही सिद्धांतों और दृष्टिकोण को लागू किया है।

प्रत्यथियों के विद्वान अधिवक्ता का इस न्यायालय के समक्ष यह कहना बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय का पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार सीमित है। इस संबंध में, साधना लोध बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य (सुप्रा.) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियां उपयोगी हैं और इसलिए, यहां नीचे उद्धृत की गई है:-

“8. संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार अदालतों केवल यह देखने तक ही सीमित हैं कि क्या एक अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने मापदंडों के भीतर आगे बढ़ा है और रिकॉर्ड का देखने से ही पता चलने वाली त्रुटि को ठीक करने के लिए नहीं,

कानून की त्रुटि से तो बिल्कुल भी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पर्यवेक्षी शक्ति का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय या न्यायाधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर याचिका पर उच्च न्यायालय को उन साक्ष्यों की समीक्षा या फिर से वजन करने की भी अनुमति नहीं है, जिन पर निचली न्यायालय या न्यायाधिकरण ने आदेश पारित किया है या निर्णयों में कानून की त्रुटियों को ठीक किया है।”

माननीय उच्चतम न्यायालय ने एल.चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और अन्य (सुप्रा.) के मामले में अपने संविधान पीठ के निर्णय में यह भी स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि पारित आदेश को चुनौती देने के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला क्षेत्राधिकार ट्रिब्यूनल द्वारा मूलतः पर्यवेक्षी प्रकृति का है। केवल कानून और तथ्यों की त्रुटि इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, जब तक कि ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश पेटेंट अवैधता, विकृति या क्षेत्राधिकार की गंभीर त्रुटि से ग्रस्त न हो।

यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि अपीलार्थी के विरुद्ध शुरू की गई विभागीय जांच दुर्भावना से प्रेरित थी। आरोप-पत्र जारी करने में क्षेत्राधिकार संबंधी प्राधिकार की अनुपस्थिति के आधार पर कोई चुनौती नहीं है।

इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इसलिए, याचिका खारिज कर दी जाती है।

(विनोद कुमार भरवानी), न्यायमूर्ति

(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव), न्यायमूर्ति

संजय कुमावत-1

टिप्पणी: इस निर्णय का हिन्दी अनुवाद निविदा फर्म **राजभाषा सेवा संस्थान** द्वारा किया गया है, जिसे फर्म के निदेशक डॉ. वी. के. अग्रवाल, द्वारा मान्य और सत्यापित किया गया है।
अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन व कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।